भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1276**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

इलायची बोर्ड की पुनर्स्थापना

1276. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **वाणिज्य और उद्योगमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलायची बोर्ड, जो इलायची किसानों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में कार्य कर रहा था, की पुनर्स्थापना करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास गत वर्ष सूखे के कारण इलायची किसानों को बड़े पैमाने पर हुए नुकसान का कोई आकलन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को सूखे से प्रभावित इलायची किसानों की सहायता के लिए केरल राज्य सरकार से सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का सूखे से प्रभावित इडुक्की के इलायची किसानों की सहायता के लिए एक नया पैकेज तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): मसाला बोर्ड का गठन मसाला बोर्ड अधिनियम,1986 के तहत, पूर्ववर्ती इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद को मिलाकर किया गया था। मसाला बोर्ड के अधिदेश में इलायची (छोटी और बड़ी) के अनुसंधान, उत्पादन, विकास, घरेलू विपणन, उपभोग और निर्यात संवर्धन के साथ-साथ 51 अन्य मसालों का निर्यात संवर्धन शामिल हैं। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मसाला बोर्ड इलायची किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां चला रहा है, जिनमें इलायची की खेती और प्रसंस्करण के उन्नत तरीकों के लिए इलायची की पुनः रोपाई और

इलायची उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता देना; इलायची उत्पादकों के बीच सहकारी प्रयास को बढ़ावा देना; इलायची परीक्षण में प्रशिक्षण प्रदान करना और इलायची के ग्रेड मानक तय करना शामिल है।

इसके अलावा, मसाला बोर्ड द्वारा 1987 में अपनी स्थापना के बाद से किए गए पहलों से छोटी इलायची का उत्पादन 1987-88 में 3200 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 25231 मीट्रिक टन; छोटी इलायची की उत्पादकता 1987-88 में 46 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 521.33 किग्रा/हेक्टेयर; छोटी इलायची के निर्यात की मात्रा 1987-88 में 270 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 6,168 मीट्रिक टन और छोटी इलायची के निर्यात का मूल्य 1987-88 में 3.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 के दौरान 999.59 करोड़ रुपये होने में मदद मिली हैं, बड़ी इलायची के मामले में उत्पादन 1987 में 2250 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 9288 मीट्रिक टन हो गई हैं; उत्पादक्ता 1987 में 96 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 288.54 किलोग्राम/हेक्टेयर हो गई; निर्यात की मात्रा 1987-88 में 155 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 1281 मीट्रिक टन हो गई और बड़ी इलायची के निर्यात का मूल्य 1987-88 में 0.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 के दौरान 148.15 करोड़ रुपये हो गया। उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि ने इलायची किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद की है।

(ग) से (छ): मसाला बोर्ड ने इडुक्की जिले में हाल ही में सूखे की वजह से हुए नुकसान का आकलन किया है। यह देखा गया है कि उचित छाया विनियमन, कैनोपी साइज और सिंचाई सुविधाओं के साथ बागान न्यूनतम नुकसान के साथ बच गए हैं।

मसाला बोर्ड को केरल सरकार से सूखे से प्रभावित इलायची किसानों को पुनः रोपण सहायता प्रदान करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। मसाला बोर्ड 'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवाचारी और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता' (स्पाईस्ड) योजना को लागू कर रहा है और उक्त योजना के तहत मसाला बोर्ड द्वारा की गई पुनः रोपण सहायता भी सूखे से प्रभावित लोगों को दी जा रही है। मसाला बोर्ड मौसम की अनिश्चितताओं के कारण इलायची उत्पादकों के नुकसान को कम करने के लिए छोटे इलायची उत्पादकों के लिए मौसम आधारित बीमा योजना लागू कर रहा है, जिसके तहत वे प्रभावित उत्पादक जिन्होंने इस योजना की सदस्यता ली है,भी इस योजना के तहत लाभ उठाएंगे।

वर्तमान में,इडुक्की इलायची किसानों के लिए किसी नए पैकेज का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

***